आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य रसंचार नेटवर्क से सम्पर्क स्थापित करने के लिए मुख्य जनजातीय क्षेत्रों में 10 उपग्रह भू-केन्द्र संस्थापित करने की योजना बनाई है।

मनाली के लिये एस०टी०डी० सुविधा

708. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन की दृष्टि से मनाली के महत्व को देखते हुए मनाली के लिये एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो मनाली को यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी, हां ।

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में मुख्य डाकघर भवन का निर्माण

709. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला के मुख्य डाकघर के भवन के निर्माण के लिए सरकार ने कुछ धनराशि स्वीकृत की थी ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि स्वीकृत हुई थी और कब;

(ग) निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) इस भवन के निर्माण के कब तक पूर्ण हो जाने की योजना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी, नहीं । मुख्य डाकघर कुल्लू के लिए भवन के निर्माण हेतु कोई धनराशि मंजूर नहीं की गई है ।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) परियोजना अभी योजना स्तर पर है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

Pending Telephone Connections on tht Recommendations of Chandrashekhar Government.

710. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA :
SHRI MOHINDER SINGH LATHER:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether there is any list still pending to provide telephone connections issued during Nov. 1990 to June, 1991 by Government on, the recommendations of State Party Presidents and by the then Communications Minister himself; and

(b) if so, what action has been taken by Government in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER. IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) :
(a) and (b) Yes, Sir. On detection of some fake cases, instructions were issued to field offices to stop all further action on these cases till the genuineness of individual cases are verified. Further action to implement the sanctions can be taken only affter, the enqyiryedn into the fake cases is completed.